



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2015/फाल्गुन 22, 1936

No. 86]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2015/PHALGUNA 22, 1936

महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 4 मार्च, 2015

सं. टीएमपी/55/2012—पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण एतद्वारा पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से इसकी मानदरों के सामान्य संशोधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव का संलग्न आदेश के अनुसार निपटारा करता है।

महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/55/2012—पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास

.....

आवेदक

(i) टी.एस. बालासुब्रह्मणियन, सदस्य (वित्त)

(ii) सी.बी. सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(13 फरवरी, 2015 को पारित)

यह मामला पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से इसकी मानदरों के सामान्य संशोधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के बारे में है।

2 पीपीटी की वर्तमान मानदरें अंतिम बार इस प्राधिकरण ने दिनांक 25 मार्च, 2011 के आदेश संख्या टीएमपी/62/2009—पीपीटी द्वारा अनुमोदित की थी। इस आदेश को भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 111 में 23 मई, 2011 को अधिसूचित किया गया था। कथित आदेश में प्रशुल्क की वैधता 31 मार्च, 2013 तक की अवधि तक निर्धारित की गई थी।

3.1 पीपीटी ने वर्तमान मानदरों के संशोधन हेतु अपना प्रस्ताव 27 अगस्त, 2012 को दायर किया। प्रस्ताव को प्रशुल्क मामले के रूप में पंजीकृत किया गया और विचार-विमर्श किया गया। प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठन से प्राप्त टिप्पणियां प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में पत्तन को भेजी गई थी। प्रस्ताव की आंतरिक जांच की गई और मामले पर संयुक्त सुनवाई 25 फरवरी, 2013 को हुई।

3.2 जब यह प्राधिकरण मामले को विचारार्थ अंतिम रूप दे रहा था, उस समय पीपीटी ने अपने दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 के पत्र द्वारा कहा कि वित्तीय वर्ष 2012-13 समाप्त हो चुका है और वर्ष 2012-13 के वास्तविक आंकड़ें उपलब्ध हैं। पीपीटी ने यह भी कहा कि संचालित किए जाने वाले अनुमानित कार्गो मिक्स में परिवर्तन हुआ है और तेल कार्गो काफी बढ़ गया है। इसके अलावा, पीपीटी ने कहा कि 12 अक्टूबर, 2013 को भीषण चक्रवात

के कारण पत्तन की संपत्तियों को नुकसान हुआ है और यदि भारत सरकार नुकसान की बहाली के लिए अनुदान के पीपीटी के अनुरोध पर विचार नहीं करती है तो पीपीटी को अपने आंतरिक संसाधनों से बहाली लागत लगानी होगी जिससे इसके आंतरिक संसाधन प्रभावित होंगे। उपरोक्त स्थिति के मध्ये नजर पीपीटी ने अपनी मानदरों के सामान्य संशोधन हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तीन माह का समय मांगा और वर्तमान मानदरों के अनुसार प्रशुल्क लगाव जारी रखने का अनुरोध किया।

3.3 पीपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर इस प्राधिकरण ने अपने दिनांक 10 जनवरी, 2014 के आदेश द्वारा पीपीटी की वर्तमान मानदरों की वैधता इसकी समाप्ति की तारीख से 31 मार्च, 2014 तक बढ़ाई बशर्ते कि आगामी चक्र हेतु निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में 1 अप्रैल, 2013 के बाद पीपीटी को स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य वसूली के ऊपर अतिरिक्त कोई अधिशेष का उपचयगत पूर्ण समायोजन हो। इस संबंध में पीपीटी को पत्तन द्वारा सहमति के अनुसार 31 जनवरी, 2014 तक इसकी वर्तमान मानदरों के सामान्य संशोधन हेतु संशोधित प्रस्ताव दायर करने का निर्देश दिया गया।

3.4 चूंकि प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था, पीपीटी को हमारे दिनांक 17 फरवरी, 2014 के पत्र द्वारा इसका संशोधित प्रस्ताव दायर करने का अनुस्मारक दिया गया। पीपीटी ने अपने दिनांक 28 फरवरी, 2014 के अपने पत्र द्वारा कहा कि वह सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए जाने वाले नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में पीपीटी को हमारे दिनांक 1 मई, 2014 के पत्र द्वारा इसे 2005 के लागू प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अपना प्रस्ताव दायर करने की सलाह दी गई।

3.5 तत्पश्चात, यह जानकर कि पीपीटी ने अपना संशोधित प्रस्ताव दायर नहीं किया है और पीपीटी द्वारा दायर किए जाने वाले संशोधित प्रस्ताव की पावती के बाद अंतिम विचारार्थ हेतु मामले को परिपक्व होने के लिए इसमें कुछ समय लगेगा, इस प्राधिकरण ने दिनांक 4 अप्रैल, 2014 के अपने आदेश द्वारा पीपीटी की वर्तमान मानदरों की वैधता इसकी समाप्ति से 30 जून, 2014 तक बढ़ाई बशर्ते कि आगामी चक्र हेतु निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में 1 अप्रैल, 2013 के बाद पीपीटी को स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य वसूली के ऊपर अतिरिक्त किसी अधिशेष का उपचयगत पूर्ण समायोजन हो।

3.6 तथापि, पीपीटी ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। यह जानते हुए कि पीपीटी द्वारा दायर किए जाने वाले संशोधित प्रस्ताव की पावती के बाद इस प्राधिकरण ने दिनांक 4 अप्रैल, 2014 के अपने आदेश द्वारा पीपीटी की वर्तमान मानदरों की वैधता इसकी समाप्ति से 30 सितंबर, 2014 तक बढ़ाई बशर्ते कि आगामी चक्र हेतु निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में 1 अप्रैल, 2013 के बाद पीपीटी को स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य वसूली के ऊपर अतिरिक्त किसी अधिशेष का उपचयगत पूर्ण समायोजन हो। पीपीटी को 2005 के लागू प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के अंतर्गत 31 अगस्त, 2014 तक अपना संशोधित प्रस्ताव दायर करने की भी सलाह दी गई।

3.7 तत्पश्चात, पीपीटी की वर्तमान मानदरों की विस्तारित वैधता 30 सितंबर, 2014 को समाप्त हो चुकी है और यह मानते हुए कि पीपीटी ने अपना संशोधित प्रस्ताव दायर नहीं किया है और यह कि पीपीटी द्वारा दायर किए जाने वाले संशोधित प्रस्ताव की प्राप्ति के बाद अंतिम विचारार्थ हेतु मामले को परिपक्व होने में समय लगेगा, इस प्राधिकरण ने दिनांक 30 सितंबर, 2014 के अपने आदेश द्वारा पीपीटी की वर्तमान मानदरों की वैधता इसकी समाप्ति से 31 दिसंबर, 2014 बढ़ाई बशर्ते कि आगामी चक्र हेतु निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में 1 अप्रैल, 2013 के बाद पीपीटी को स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य वसूली के ऊपर अतिरिक्त किसी अधिशेष का उपचयगत पूर्ण समायोजन हो। पीपीटी को अपना संशोधित प्रस्ताव शीघ्र दायर करने की भी सलाह दी गई।

3.8 तत्पश्चात, इस प्राधिकरण ने अपने दिनांक 02 जनवरी, 2015 के आदेश द्वारा पीपीटी की वर्तमान मानदरों की वैधता 31 मार्च, 2015 तक बढ़ाई बशर्ते कि आगामी चक्र हेतु निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में 1 अप्रैल, 2013 के बाद पीपीटी को स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य वसूली के ऊपर अतिरिक्त किसी अधिशेष का उपचयगत पूर्ण समायोजन हो।

4. इसी बीच पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने दिनांक 13 जनवरी, 2015 के पत्र संख्या 8 (1)/2014-टीएमपी द्वारा 'महापत्तन न्यासों हेतु प्रशुल्क निर्धारण की नीति, 2015' जारी की जिसे इस प्राधिकरण ने 27 जनवरी 2015 को राजपत्र संख्या 30 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। नई 'महापत्तन न्यासों हेतु प्रशुल्क निर्धारण की नीति, 2015' 13 जनवरी, 2015 से प्रभावी हुई।

5.1 यह मानते हुए कि इस प्राधिकरण को पीपीटी से अभी संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होना है और नई प्रशुल्क नीति, 2015 चूंकि प्रभाव में आ गई है, पीपीटी को अपना संशोधित प्रस्ताव पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा घोषित नई प्रशुल्क नीति, 2015 के अनुरूप बनाना होगा। पीपीटी का प्रस्ताव जब कभी प्राप्त होगा, उसे नई प्रशुल्क नीति, 2015 अपनाते हुए संसाधित किया जाना होगा।

5.2 उपरोक्त स्थिति के मद्दे नजर यह प्राधिकरण पीपीटी का वर्तमान प्रस्ताव बंद करने का निर्णय लेता है। पीपीटी को प्रशुल्क नीति, 2015 के आधार पर अपना संशोधित प्रस्ताव दायर करने की भी सलाह दी जाती है। पीपीटी से संशोधित प्रस्ताव, जब कभी प्राप्त होगा, उस पर नए सिरे से विचार किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रह्मणियन, सदस्य (वित्त)

[ विज्ञापन—III/4/असा./143/2014 (325) ]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 4th March, 2015

**No. TAMP/55/2012-PPT.**—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Paradip Port Trust (PPT) for general revision of its Scale of Rates, as in the Order appended hereto.

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****Case No. TAMP/55/2012-PPT****Paradip Port Trust**

- - -

**Applicant****QUORUM:**

- (i) Shri. T. S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. C. B. Singh, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on this 13th day of February, 2015)

This case relates to the proposal received from the Paradip Port Trust (PPT) for general revision of its Scale of Rates (SOR).

2. The existing SOR of the PPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/62/2009-PPT dated 25 March, 2011. This Order was notified in the Gazette of India on 23 May, 2011 vide Gazette No. 111. The said Order prescribed a tariff validity period till 31 March, 2013.

3.1. The PPT filed its proposal for revision of the existing SOR on 27 August, 2012. The proposal was registered as a tariff case and taken on consultation. The comments received from user/ user organization was forwarded to the Port as feedback information. The proposal was internally scrutinized and joint hearing in this case was held on 25 February, 2013.

3.2. When the case was being firmed up for final consideration of this Authority, the PPT vide its communication dated 30 October, 2013 submitted that the financial year 2012-13 is already over and the actual figures for the year 2012-13 are available. The PPT also stated that the cargo mix estimated to be handled has undergone change and the oil cargo has increased substantially. Further, the PPT submitted that due to the severe cyclone on 12 October, 2013, port has suffered damages to its properties and incase if the Government of India does not consider the request of PPT for a grant to restore the damages caused, the PPT will have to meet the restoration cost from its internal resources which will affect its internal resources. In view of the above position, the PPT sought three months' time to submit a revised proposal for general revision of its SOR and requested for continuation of levy of tariff as per existing SOR.

3.3. Based on the request made by the PPT, this Authority vide its Order dated 10 January, 2014, extended the validity of the existing SOR of the PPT from the date of its expiry till 31 March, 2014, subject to full adjustment of any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return accruing to the PPT post 1 April 2013, in the tariff to be fixed for the next cycle. The PPT was also directed to file its revised proposal for general revision of its existing SOR by 31 January, 2014, as agreed by the Port.

3.4. Since the proposal was not received, the PPT was reminded vide our letter dated 17 February, 2014, to file its revised proposal. The PPT vide its letter dated 28 February, 2014 stated that it would submit its proposal as per new guidelines likely to be finalised by the Government. In this regard, the PPT was advised vide our letter dated 1 May, 2014 to file its proposal under the applicable tariff guidelines of 2005.

3.5. Thereafter, noting that the PPT has not filed its revised proposal and that it would take time for the case to mature for final consideration after receipt of the revised proposal (to be) filed by the PPT, this Authority vide its Order dated 4 April, 2014, extended the validity of the existing SOR of the PPT from the date of its expiry till 30 June, 2014, subject to full adjustment of any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return accruing to the PPT post 1 April, 2013, in the tariff to be fixed for the next cycle.

3.6. However, the PPT had not submitted its proposal. Recognizing that it would take time for the case to mature for final consideration after receipt of the revised proposal (to be) filed by the PPT, this Authority vide its Order dated 4 July, 2014, extended the validity of the existing SOR of the PPT from the date of its expiry till 30 September 2014, subject to full adjustment of any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return accruing to the PPT post 1 April, 2013, in the tariff to be fixed for the next cycle. The PPT was also advised to file its revised proposal by 31 August 2014 under the applicable tariff guidelines of 2005.

3.7. Subsequently, since the extended validity of the existing SOR of PPT has expired on 30 September, 2014 and recognizing that the PPT had not filed its revised proposal and that it would take time for the case to mature for final consideration after receipt of the revised proposal (to be) filed by the PPT, this Authority vide its Order dated 30 September, 2014 extended the validity of the existing SOR of the PPT from the date of its expiry till 31 December,

2014, subject to full adjustment of any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return accruing to the PPT post 1 April, 2013, in the tariff to be fixed for the next cycle. The PPT was also advised to file its revised proposal at the earliest.

3.8. Thereafter, this Authority vide its Order dated 2 January, 2015 has extended the validity of the existing SOR of the PPT till 31 March 2015, subject to full adjustment of any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return accruing to the PPT post 1 April, 2013, in the tariff to be fixed for the next cycle.

4. In the meantime, the Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No. 8(1)/2014-TAMP dated 13 January, 2015 has issued the new “Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015. This has been notified in the Gazette of India vide Gazette No. 30 dated 27 January, 2015 by this Authority. The new “Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015” has come into effect from 13 January, 2015.

5.1. Given that this Authority is yet to receive the revised proposal from PPT and also since the new Tariff Policy, 2015 has come into effect, the PPT would have to formulate its revised proposal in accordance with the new Tariff Policy of 2015 announced by the MOS. The proposal of PPT as and when received would have to be processed following the new Tariff Policy, 2015.

5.2. In view of the above position this Authority decides to close the current proposal of PPT. The PPT is advised to file its revised proposal based on the Tariff Policy, 2015. The revised proposal as and when received from PPT, would be treated afresh.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT III/4/Exty./143/2014 (325)]